कौशल भारत में तत्काल सुधारों की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

ऐसा माना जा रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा में सुधार किये बिना देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित दोहन नहीं कर सकता है, अतः भारतीय जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित उपयोग, भारत के विकास की कहानी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिये। इसी संदर्भ में वर्ष 2016 में भारत सरकार ने क्षेत्र कौशल परिषद (Sector Skill Councils -SSCs) को तर्कसंगत बनाने के लिये शारदा प्रसाद समिति का गठन किया था। ध्यातव्य है कि अब एक साल बाद, समिति के प्रमुख सुझावों और व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण (vocational education/training - VET) प्रणाली में कार्रवाई करना विवेकपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

क्षेत्र कौशल परिषद (Sector Skill Councils - SSCs) क्या है ?

- ये उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा राष्ट्रीय पेशागत मानकों/सक्षमता मानकों और योग्यता को विकसित करते हैं।
- राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति, 2015 के तहत दिये गए अधिदेश के अनुसार एसएससी का अभिसरण एवं इष्टतम कामकाज सुनिश्चित करने के लिये एक समिति के गठन का फैसला किया गया था।
- इस समिति का कार्य एसएससी के कामकाज की समीक्षा करना तथा उनके समग्र विकास के लिये एक रोड मैप उपलब्ध कराना था, जिससे कि कौशल प्रणाली का कारगर विकास सुनिश्चित किया जा सके।

शारदा प्रसाद समिति

- इस समिति का गठन भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के पूर्व महानिदेशक श्री शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में 18 मई, 2016 को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तीन खंडों में उपलब्ध है। मुख्य रिपोर्ट पहले खंड में है, जो देश की व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली के सामने आ रही बड़ी चुनौतियों तथा क्षेत्र कौशल परिषदों के संयोजन, समन्वय एवं विवेकीकरण से संबंधित है।
- दूसरे खंड में अध्यायवार परिशिष्टों का संकलन किया गया है। तीसरे खंड में राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के साथ राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण के मानचित्र दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- कौशल भारत योजना के दो प्रमुख लक्ष्य हैं - पहला, ऐसे नियोक्ता की तलाश करना जिसे कौशल की आवश्यकता है ।
- दूसरा, एक सभ्य आजीविका के लिये श्रमिकों (युवा और बुज़ुर्ग) को तैयार करना ।
- रिपोर्ट में बार-बार युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। साथ ही सिफारिश में इस बात पर जोर दिया गया है कि वीईटी केवल वंचित समुदायों के लिये ही नहीं है; यह उन लोगों के लिये भी है जो इसे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते (यह हम सभी के लिये है)।

रिपोर्ट संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश

छात्रों के लिये स्ट्रीमिंग

- यह रिपोर्ट मानसिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिये ठोस कदमों का सुझाव देता है, जैसे व्यावसायिक शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा में) के लिये एक अलग विभाग, व्यावसायिक स्कूलों और व्यावसायिक कॉलेजों को ऊपर की ओर गतिशील बनाने के लिये तथा डिग्री प्राप्त करने के लिये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
- स्ट्रीमिंग का आशय 'डिप्लोमा बीमारी (diploma disease) से है , जिसके परिणामस्वरूप शिक्षितों के बीच बढ़ती बेरोज़गारी के साथ ही तृतीयक नामांकन दर में भी वृद्धि हो रही है।
- उदाहरण के लिये चीन में नौ साल की अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद एक अलग विभाग है और आधे छात्रों ने उच्च माध्यमिक स्तर (9 वीं के बाद) में वीईटी का चयन किया है।
- वीईटी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तंभ के लिये निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (vocational training providers - VTPs), निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (industrial training institutes - ITIs) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation - NSDC) के रूप में उभर रहे हैं।
- इसके लिये छोटे-समय के प्रशिक्षण प्रदाता और उद्योग-नियोक्ताओं के मध्य मज़बूत गठजोड़ की आवश्यकता है।

एक वैश्वकि संरेखण (A global alignment)

- एक मुख्य वषिय मानव क्षमता का अहसास करना है अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को संरेखति करना, 3 आर का बुनयिादी आधार सुनश्चिति करना और जीवनभर सीखने की क्षमता।
- यह एक मांग आधारति कौशल सेट के लयि राष्ट्रीय मानकों को दर्शाता है जो राष्ट्रीय/वैश्वकि गतशिीलता के साथ बेहतर नौकरयिों में रूपांतरति होती हैं।
- मुख्य ध्यान पढ़ने, लखिने और अंकगणति कौशल को मज़बूत करने में होना चाहयि। यदि देश का अधकिांश कार्यबल फास्ट-चेंजगि दुनयिा के अनुकूल कौशल का नरि्माण नहीं कर पाता, तो कोई भी कौशल वकिास सफल नहीं हो सकता है।
- वोकेशनल ट्रेनगि को न्यूनतम एक साल के लयि परभिाषति करना चाहयि, जसिमें इंटर्नशपि शामलि हो (जसिके बनिा प्रमाणीकरण संभव नहीं है)।
- अल्पकालकि प्रशक्षिण को पहले से ही काम कर रहे अनौपचारकि रूप से प्रशक्षिति श्रमकिों के रूप में पहचानने तक ही सीमति रखा जाना चाहयि।
- दूसरा वषिय ऐसे समय में सही कार्य करना है, जब कोई नयिामक संस्था आपको नहीं देख रही होती है, क्योंकि अन्य औद्योगकि क्षेत्रों में नयिामक ने वनियिमति करने की सीमति क्षमता ही प्रदर्शति की है। ऐसे में हतिों के संघर्ष और पेपर पर आयोजति होने वाले प्रशक्षिण के मामले भी नए नहीं हैं।
- नजिी आईटीआई पर हालयि संसदीय रपिोर्ट ने एक और घोटाले का खुलासा कयि है जसिमें हज़ारों नजिी आईटीआई के लयि भारत की गुणवत्ता परषिद ने मंजूरी दी। यह इस तरह के आईटीआई में गुणवत्ता के प्रशक्षिण की कमी के साथ वनियिमन की भारी वफिलता को इंगति करता है।
- क्षेत्रीय कौशल परषिदों की अधकिता और एक वशि्वसनीय मूल्यांकन बोर्ड की अनुपस्थतिि से एक बड़ी नैतकिता और जवाबदेहति का संकट उत्पन्न होता है, ऐसे में प्रत्येक अपने व्यवसाय को अधकितम लाभ पहुँचाने की कोशशि करता है।

एकीकरण के लयि प्रयास

- पहला नीतगित कदम पूरे वीईटी सस्टिम के एकीकरण की दशिा में होना चाहयि। 'स्कलि इंडयिा' केवल तब प्रभावकारी हो सकता है जब इसके सभी स्तंभ एक साथ मलिकर काम करें और एक-दूसरे से सीखें।
- एसएससी जसिे उद्योग के प्रतनिधि संस्था के रूप में माना जाता है, को सस्टिम के प्रत्येक स्तंभ के साथ सामंजस्य बनाना चाहयि, न केवल एनएसडीसी द्वारा वत्तिपोषति वीटीपी के साथ ।
- दूसरा कदम नयिोक्ता के स्वामतिव, ज़म्मिेदारी और प्राप्त परणिामों में उनके स्वयं की लाभ प्राप्ति('skin in the game') को बढ़ाने के लयि है।
- मीडयिा रपिोर्टों में अक्सर "बेरोज़गार युवाओं" की ओर कॉर्पोरेट क्षेत्र का ध्यान आकर्षति करने की कोशशि की गई है, (नजिी क्षेत्र इसे सरकार की ज़म्मिेदारी समझता है, जबकि सरकार नजिी क्षेत्र की और देखती है)।
- इसका नतीजा यह है कि भारत की संगठति क्षेत्र की कंपनयिाँ केवल 36% फर्म प्रशक्षिण आयोजति करती हैं (इसमें ज़्यादातर बड़े फर्म हैं, जो कि केवल भारत सरकार अधनियिम के तहत शकि्षिुओं को लेते हैं)।
- इसके लयि समतिि की सफिारशि के अनुसार एक प्रतपिूर्ति योग्य उद्योग योगदान मॉडल (केवल संगठति क्षेत्र पर लागू) की व्यवस्था द्वारा एक सामान्य स्तर का क्षेत्र प्रदान करते हुए इस समस्या का समाधान कयि जाना चाहयि।
- तीसरा नीतगित कदम यह समझने में है कि सरकार को वत्तिपोषण और प्रबंधन करने में दशकों बीत चुके हैं और अब सरकार को आपूर्ति-चालति प्रणाली की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्षेत्र द्वारा डेटा एकत्र करना

- सरकार, जो सार्वजनकि क्षेत्र में न तो ज्यादा रोज़गार पैदा कर रही है और न ही नजिी क्षेत्र में उद्योग के लयि कौशल की आवश्यकताओं को समझ पा रही है। ऐसे में सरकार को स्वयं को कल्याणकारी भूमकिाओं तक सीमति रखने की ज़रूरत है।
- हालाँकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार, कौशल प्रदाताओं के वभिन्नि क्षेत्रों द्वारा कौशल प्रदान करने और कौशल अंतराल के आँकड़ों को एकत्रति करने जैसे डेटा साक्ष्य-आधारति नीति-नरि्माण को सरकार मार्गदर्शन दे सकती है।

नष्किर्ष

अंततः, हमें स्कलिगि पहल द्वारा वास्तवकि मूल्य में हतिधारकों से अधकि भागीदारी कयि जाने की आवश्यकता है। एनएसडीसी, जसिे सार्वजनकि-नजिी साझेदारी के रूप में देखा गया था, अपने धन का 99% सरकार से प्राप्त करता है, लेकनि इसकी प्रमुख योजना में प्रशक्षिुओं के लयि नयिुक्ति 12% से भी कम रकिॉर्ड है। भारत नश्चिति रूप से दुनयिा की कौशल पूंजी बन सकता है और इस दशिा में समतिि द्वारा सुझाए गए सुधारों को एक अच्छा प्रारंभकि बदिु माना जा सकता है।

प्रश्न: अधकिांश देशों में कार्यबल फ़ास्ट चेजगि दुनयिा के अनुकूल न होने के कारण उन देशों में कौशल वकिास की सफलता संदेहास्पद बनी रहती है। इसी संदर्भ में शारदा प्रसाद समतिि द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं पर टप्पिणी करें।

इससे संबंधति अधकि जानकारी के लयि इन लकि्स का प्रयोग करें -

⇒ क्षेत्र कौशल परषिदों (Sector Skill Councils) की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इस संबंध में शारदा प्रसाद समतिि की अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्त्व पर चर्चा करें।

⇒ कौशल वकिास और उद्यमति मंत्रालय की वार्षकि समीक्षा

⇒ प्रश्न. प्रधानमंत्री कौशल वकिास योजना, भारत को जनसांख्यकिीय लाभांश का फायदा दलिाने में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिा सकती है। इसके समक्ष मौजूद चुनौतयिों का उल्लेख करें तथा उनसे नपिटने के लयि उपाय भी सुझाएँ।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/skill-indiai-urgently-needs-reforms